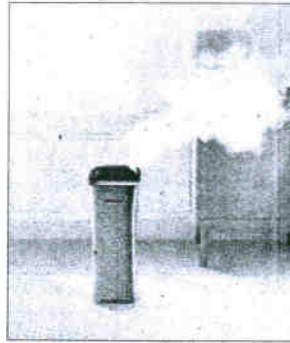


## Air purifier market to touch \$39 mn by 2023

**NEW DELHI:** India's residential air purifiers market is projected to grow at a CAGR of over 29 per cent from the current \$14.14 million to \$38.99 million by 2023, backed by rapid urbanisation, increased purchasing power, expanding urban population and deteriorating air quality, according to a report.

The Assocham-TechSci Research joint study said some other key factors expected to drive the market are growing technological advancements, aggressive marketing strategies by air purifier companies, increasing incidences of airborne diseases and aspiration to lead a healthier lifestyle which is anticipated to boost demand.

The residential sector accounted for a revenue share of around 22 per cent in the overall India air purifiers market in 2017, on account of increasing airborne disease in the country, due to rising air pollution, according to the report. The presence of high concentration of PM2.5 and



PM10 in the air leads to high pollution levels in northern parts of India, especially Delhi-NCR, which is among the most polluted regions in the country. As a result, demand for residential air purifiers from northern India is increasing, the study said.

In 2017, industrial air filters market stood at \$293.27 million and is forecast to grow at a CAGR of 6.07 per cent to cross \$392.63 million by 2023. Also, the need for frequent replacement of air filters in the construction sector is spurring demand for air filters, noted the joint study. P11

B K Goenka

The Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) play a vital role in the growth of Indian economy by contributing 45 per cent of the industrial output, 40 per cent of exports, creating one million jobs every year and producing more than 8,000 quality products for the Indian and international markets.

While the large

number of MSMEs and their contribution present immense potential, they are beset with challenges, which when addressed would unleash this capability to propel India's economic growth significantly.

The share of SMEs in India's GDP at 8-10 per cent pales in comparison with developed economies such as US, France or Germany, where this share is almost 50 per cent. Obviously then,

there is more room for improvement in the Indian context. Before we attempt to delve into possible remedies, let's first look at the challenges faced by MSMEs.

**CHALLENGING SCENARIO**

One of the primary challenges that most MSMEs face is access to cheaper funds. MSMEs in our country continue to struggle with traditional banking impediments. Indian banks charge

## FINANCIAL OUTREACH PROGRAMME FOR MSME NEED OF THE HOUR

India's 6.3 crore MSME sector contributes around 8-10 per cent to the GDP, employs almost 11 crore workforce and has a major role in boosting initiatives like 'Make in India'



about 9 and 16 per cent, while NBFCs - bank-like financing institutions - most of which do not accept deposits, charge up to 24 per cent, which hurts the competitiveness of these MSMEs. In comparison, interest rates in Europe are as low as 2-2.5%.

Non-banking financial companies (NBFCs) used to be a major source of funds for small businesses. After the I&FS default on loan repayments,

the government superseded its board, which saw liquidity crises widening for these MSMEs. The norms for NBFCs have been tightened, impacting the credit availability to the sector further.

MSMEs also face challenges in raising funds from non-bank finance instruments, especially from capital market. The total financing demand of Indian MSME sector is Rs 32.5 lakh crore. However, the availability of funds from formal finance sources is around Rs 14.6 lakhs. This credit gap of 56 per cent is significantly affecting the growth of MSMEs.

Borrowing funds from banks have met their share of hiccups in the form of longer processing times, lack of trans-

parency in timelines, and insufficient loan sizes. These issues compel many MSMEs to continue seeking funds from informal sources, and unfortunately at much higher interest rates, which are over 2.5 times higher than those in the formal sector.

**UNSHACKLING THE MSME POTENTIAL**

There is, however, a silver lining. To promote the MSME sector including other organized segments, the government has come out with many initiatives like the Make in India programme where serious efforts have been undertaken to provide growth opportunities to set up and scale their business spanning various sectors. Sectors such as industrial manufac-

turing, foundry and electricals, agro and food processing, electronics, chemicals, leather and textiles, defence & aviation, and many more, have contributed directly/indirectly to these initiatives.

In November 2018, the Prime Minister

announced schemes to promote MSME sector in India. Primary among them being the 2 per cent interest subvention or rebate on incremental loan of up to Rs 1 crore for all GST-registered MSMEs.

Another scheme with 59-minute loan

facility of up to Rs 1 crore for small and medium entrepreneurs is also a step in the right direction. Till December 2018, it was reported that state-run banks have given in-principle approval to 1.12 lakh loan applications of MSMEs, totalling Rs

37,412 crore, under the scheme.

Due to these initiatives, a favourable ecosystem has been created for SMEs.

The author is President, ASSOCHAM

Resp. edit @timesgroup.com

### FUNDING WOES

- Indian banks charge about 9% & 16%, while NBFCs charge up to 24%. In comparison, interest rates in Europe are as low as 2-2.5%
- Post I&FS, default on loan repayments, government superseded its board, which saw liquidity crises widening for MSMEs
- MSMEs also face challenges in raising funds from non-bank finance instruments, especially from the capital market

## एयर प्यूरिफायर मार्केट हासिल करेगा 29% ग्रोथ

नई दिल्ली: डोमेस्टिक रेजिडेंटल एयर प्यूरिफायर मार्केट की ग्रोथ 29 पर्सेंट CAGR से ज्यादा रह सकती है। इससे

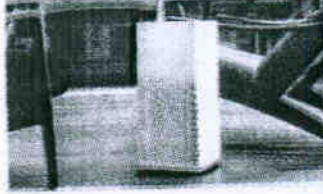


मौजूदा \$1.414 करोड़ का यह बाजार 2023 तक \$3.899 करोड़ पर पहुंच जाएगा। एक रिपोर्ट में इसकी वजह तेजी

से बढ़ते शहरीकरण, बढ़ती क्रयशक्ति, शहरी जनसंख्या में तेज वृद्धि और हवा की बिगड़ती गुणवत्ता बताई गई है। एसोचैम और टेकसाई रिसर्च ने इसको लेकर एक संयुक्त स्टडी की है। एयरप्यूरिफायर की डिमांड में तेजी से बढ़ती एडवांसमेंट और एयर प्यूरिफायर कंपनियों की आक्रामक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का अहम रोल होगा। इसमें हवा से फैलने वाली बीमारियों और लोगों की स्वास्थ्यवर्धक जीवनशैली की चाहत से भी डिमांड बढ़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक, वायु प्रदूषण के चलते होनेवाली बीमारियों के मद्देनजर 2017 में कुल एयर प्यूरिफायर मार्केट में रेजिडेंशियल सेक्टर का शेयर करीब 22 पर्सेंट था। स्टडी के मुताबिक उत्तर भारत, खासतौर पर देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित इलाके दिल्ली-एनसीआर की हवा में PM2.5 और PM10 की मात्रा बढ़ने से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। इससे यहां रेजिडेंटल एयर प्यूरिफायर्स की मांग बढ़ रही है।



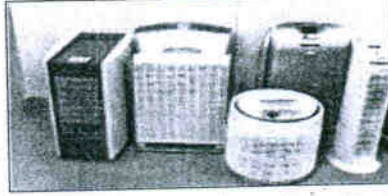
## एयर प्योरिफायर 2023 तक 276 करोड़ का हो सकता है बाजार



नई दिल्ली @ पत्रिका. उद्योग मंडल एसोसिएम एवं टेकसाई रिसर्च के एक संयुक्त अध्ययन से पता चला है कि वायु प्रदूषण, तेजी से हो रहे शहरीकरण आदि के कारण भारत का घरेलू एयर प्योरिफायर बाजार में वृद्धि आएगी। एक अनुमान के मुताबिक साल 2023 तक साल दर साल 29 फीसदी की वृद्धि के साथ यह बाजार बढ़कर करीब 276 करोड़ रुपए का हो सकता है। अभी भारत में एयर प्योरिफायर बाजार करीब 100 करोड़ रुपए का है। उत्तर भारत मांग सबसे ज्यादा बढ़ी है।

## देश का एयर प्यूरीफायर बाजार वर्ष 2023 तक 3.9 करोड़ डॉलर का हो सकता है

नई दिल्ली, 24 फरवरी (एजेंसी): भारत का घरेलू एयर प्यूरीफायर बाजार तेजी से शहरीकरण, खरीद शक्ति में वृद्धि, शहरी जनसंख्या में बढ़ती और वायु प्रदूषण की समस्याओं के बीच 2023 तक साल-दर-साल 29 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 3.899 करोड़ डॉलर का हो सकता है। वर्तमान में यह बाजार 1.414 करोड़ डॉलर का है।



उद्योग मंडल एसोसिएम एवं टेकसाई रिसर्च के संयुक्त अध्ययन में कहा गया है कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रही बेहतरी, एयर प्यूरीफायर कंपनियों की आक्रामक विपणन रणनीति, वायु प्रदूषण से बीमारियों में वृद्धि और बेहतर जीवनशैली की आकांक्षा बाजार को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाले कारक रहेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 में भारत के कुल एयर प्यूरीफायर बाजार में घरेलू क्षेत्र की हिस्सेदारी 22 प्रतिशत रही।

# 2023 तक 3.90 करोड़ डॉलर का हो सकता है एयर प्यूरिफायर कारोबार

नई दिल्ली, 24 फरवरी (एजेंसिया)। शहरों में बढ़ती आबादी और वायु गुणवत्ता में आई गिरावट के कारण देश में एयर प्यूरिफायर कारोबार के 29 प्रतिशत से अधिक की वार्षिक दर से बढ़ती करतें हुए वर्ष 2023 तक 3.90 करोड़ डॉलर के होने का अनुमान है। उद्योग संगठन एसोचैम व टेकसाई की आज जारी संयुक्त रिपोर्ट 'बायो मेडिकल वेस्ट एंड एयर पॉल्यूशन' के मुताबिक मौजूदा समय में देश में एयर प्यूरिफायर का कारोबार 1.41 करोड़ डॉलर का है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस तरह से शहरों में आबादी बढ़ रही है, शहरीकरण बढ़ रहा है, लोगों की खरीद क्षमता बढ़ रही है और वायु की गुणवत्ता घट रही है, वैसी स्थिति में एयर प्यूरिफायर कारोबार 29 प्रतिशत से



अधिक की वार्षिक दर से वृद्धि करेगा। इसके अलावा प्रौद्योगिकी उन्नयन, एयर प्यूरिफायर कंपनियों की विपणन नीति, हवा से फैलनी वाली बीमारियों की बढ़ती संख्या और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के प्रति लोगों की बढ़ती ललक के कारण भी एयरप्यूरिफायर के कारोबार को बढ़ाने में सहायक साबित होंगी। रिपोर्ट के अनुसार, घर के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर वायु प्रदूषण के बढ़ने के कारण दमे और फेफड़े के मरीजों की संख्या बढ़ रही है जो घरों के

- एसोचैम व टेकसाई की जारी संयुक्त रिपोर्ट में खुलासा
- मौजूदा समय में देश में एयर प्यूरिफायर का कारोबार 1.41 करोड़ डॉलर का है

भारत-चीन जैसे विकासशील देशों व अफ्रीका महाद्वीप का कुल कार्बन उत्सर्जन में योगदान जारी रहेगा। वायु प्रदूषण की समस्या विकासशील और विकसित दोनों के देशों के लिए चुनौतीपूर्ण है : एसोचैम

लिए एयरप्यूरिफायर की आपूर्ति करने वाली कंपनियों के लिए लाभकारी है। वर्ष 2017 में एयर प्यूरिफायर के

राजस्व में रिहाइशी इलाकों के क्षेत्र की हिस्सेदारी 22 प्रतिशत से अधिक थी। रिपोर्ट के मुताबिक देश के पूर्वोत्तर इलाके खासकर दिल्ली व एनसीआर में पीएम 2.5 और पीएम 10 वायुमंडलीय कणों की बढ़ती हुई मात्रा के कारण ये देश के सबसे प्रदूषित इलाके बने हुए हैं। इसी वजह से इन इलाकों के रिहाइशी इलाकों में एयर प्यूरिफायर की मांग बढ़ी है। वर्ष 2017 में औद्योगिक क्षेत्र में एयर प्यूरिफायर का कारोबार 29.33 करोड़ डॉलर का था जिसके 6.07 प्रतिशत की दर से बढ़ते हुए वर्ष 2023 तक 39.26 करोड़ डॉलर के होने का अनुमान है। निर्माण क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले एयर फिल्टर को ब्यार-बार बदलने की जरूरत के कारण एयर फिल्टर की मांग भी बढ़ी है।



## देश का एयर प्यूरिफायर बाजार वर्ष 2023 तक 3.9 करोड़ डॉलर का हो सकता है : रपट

नई दिल्ली, (भाषा)। भारत का घरेलू एयर प्यूरिफायर बाजार तेजी से शहरीकरण, खरीद शक्ति में वृद्धि, शहरी जनसंख्या में बढ़ोतरी और वायु प्रदूषण की समस्याओं के बीच 2023 तक साल दर साल 29 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 3.899 करोड़ डॉलर का हो सकता है। एक रपट में यह दावा किया गया है। वर्तमान में यह बाजार 1.414 करोड़ डॉलर का है। उद्योग मंडल एसोचैम एंव टेकसाई रिसर्च के संयुक्त अध्ययन में कहा गया है कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रही बेहतरी, एयर प्यूरिफायर कंपनियों की आक्रामक विपणन रणनीति, वायु प्रदूषण से बीमारियों में वृद्धि और बेहतर जीवनशैली की आकांक्षा बाजार को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाले कारक रहेंगे।